Indentification of Iron and Steel Belt by National Council of Applied Economic Rasearch

316. SHRI K. P. SINGH DEO : Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state :

(a) whether the National Council of Applied Economic Research has identified the Iron and Steel Belt in India;

(b) if so, the areas thus identified and the salient features of these areas;

(c) whether transport and communication has been indentified as one of the integral factors in the development of these areas; and

(d) if so, the main requirements of these areas and the steps taken by Government to provide transport and communication to develop and to exploit the Iron aud Steel Belt in the conntry ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) to (d). The Ministry is not aware of any such identification on the iron and steel belt in India done by National Council of Applied Economic Research. However, the Council is being asked to confirm.

विदेशी सहयोग पर उद्योगों का आश्रित रहना

317. **श्री सूरज भान :**
श्री बृज भूषण लाल :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री शारदा नन्द :

क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय-इंजीनियरिंग परिषद ने श्रीनगर में हुए हाल ही के अधिवेशन में इस तथ्य पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र, इंजीनियरिंग कारखाने स्थापित करने के मामले में विदेशी सहयोग तथा उनकी सलाह पर अधिक आश्रित रहते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि परिषद का यह मत है कि विदेशों पर इस प्रकार आश्रित रहने से भारतीय इंजीनियरों का मनोबल गिरा है बेरोजगारी बढ़ी है तथा स्वयं कारखानों को भारी हानि पहुंची है तथा इस सन्दर्भ में बोकारो इस्पात कारखाना, ईंडियन ड्रग्स एण्ड फारमस्यूटिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार तथा माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के ने नाम उल्लेखनीय है, और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) और (ख). सरकार को इस विषय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की जानकारी है ।

(ग) सरकार के विचार में यह आलोचना न्यायोचित नहीं है तकनीकी जानकारी के प्रवाह के प्रश्न पर भारत में हुए विकास तथा भारतीय उद्योगों में इसके अभाव के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए । सरकार की यह नीति रही है कि ऐसे उद्योगों में विदेशी सहयोग तथा विदेशी परामर्श को प्रोत्साहित न किया जाए जिनके लिए आवश्यक तथा उपयुक्त तकनीकी जानकारी देश में ही उपलब्ध हो । यद्यपि विदेशी सहयोग के प्रति सरकार की आधारभूत नीति मुख्यतः विगत वर्षों जैसी ही है तथापि देश में स्थापित हो चुके सशक्त औद्योगिक

आधार और देशीय अनुसन्धान तथा तकनालोजी के विकास की आवश्यकता को देखते हुए इसे प्रयास मात्रा में नया रूप दिया गया है । विदेशी सहयोग प्रस्तावों की स्वीकृति में अब न केवल अधिक चयनात्मकता बरती जा रही है बरन् इस के लिए विशिष्ट तथा स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्तों का निरूपण किया गया है । तकनीकी सहयोग के करार अब सामान्यत: उत्पादन प्रारम्भ होने से 5 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किए जाते है ताकि भारतीय एकक इस जानकारी को यथा शीघ्र ग्रहण कर सकें तथा भारतीय उत्पादनकारी एककों को अपने अनुसंधान तथा विकास सुविधाओं की स्थापना के लिए प्रोत्साहन मिले । भारतीय परामर्श-दात्री सेवाओं का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से विदेशी परामर्शदात्री सेवाओं की अनुमति केवल उन्हीं क्षेत्रों में दी जाती है, जिन में भारतीय परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं । वहां भारतीय परामर्शदात्री सेवाओं के अतिरिक्त विदेशी परामर्शदात्री सेवाएं आवश्यक हो तो उसमें यह शर्त लगा दी जाती है कि ऐसी परियोजनाओं में भारतीय परामर्श-दाताओं को भी सम्बद्ध किया जाए और यह नियम होना चाहिए कि ऐसी परियोजनाओं में भारतीय परामर्शदाता परामर्श हेतु प्रमुख अभिकरण हो ।

Demand for a Divisional Office at Rangiya Jn. (N. E. F. Railway)

818. SHRI HEM BARUA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a deputation on behalf of the citizens of Rangiya (Assam) waited upon him during the recent visit to Gauhati and apprised him of the demand for a Railway Division at Rangiya; and

(b) if so, his reaction to the demand ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) Yes.

(b) A new division at Rangiya could perhaps start functioning from 2nd October, 1971 subject to the condition that suitable land is made available by the Government of Assam in time.

Broad Gauge line to Dibrugarh N. E. F. (Rly.)

319. HEM BARUA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have decided to extent the North-East Frontier Railway Board Gauge Railway line to Dibrugarh in Assam; and

(b) if so, the details of the project ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) and (b). The conversion of the Bongaigaon-Gauhati Metre Gauge section into Broad Gauge has been included in the Railways' Perspective Plan on gauge conversion to be implemented in the next ten years or so, Surveys for this conversion have already been carried out and the reports thereof are at present under examination of the Railway Board. A decision regarding the conversion will be taken after the examination has been completed. Actual conversion of the section is also dependant upon the priority this work will merit *vis-a-vis* other conversion proposals and the availability of funds. There is no proposal at present under consideration to extent the B. G. line upto Dibrugarh. This will arise only if and when a decision is taken regarding the extension of the B. G. line upto Gauhati in the first instance.

Increase in Prices of Cycles

320. SHRI HEM BARUA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Govern-